भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *122

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

मुद्रास्फीति, आय में स्थिरता और आर्थिक असमानता से निपटना

***122. श्री विवेक के. तन्खा:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान, आर्थिक वृद्धि के बावजूद, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की लागत में निरंतर वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से अधिक रही है, यदि हां, तो सरकार निम्न आय वाले परिवारों पर पड़ने वाले बोझ को किस प्रकार कम करेगी;

(ख) आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के प्रभाव को कम करने के लिए मध्यम और निम्न आय समूहों को कोई राहत नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं और उनके वित्तीय दबाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) हाल ही में मजदूरी में 2.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से हो रही वृद्धि को देखते हुए उनकी वास्तविक आय में वृद्धि करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) कामकाजी और मध्यमवर्गीय आबादी को संबल प्रदान करने वाली एक निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ)**:** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"मुद्रास्फीति, आय में स्थिरता और आर्थिक असमानता से निपटना" विषय पर श्री विवेक के. तन्खा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) तक तीन वर्षों के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.6 प्रतिशत रही, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य की अधिसूचित अधिकतम सीमा से 6 प्रतिशत कम है। वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.9 प्रतिशत रही। विविध घरेलू वस्तुओं (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) और सेवाओं में मुद्रास्फीति को दर्शाने वाली प्रमुख मुद्रास्फीति जनवरी 2025 तक लगातार 14 महीनों के दौरान 4 प्रतिशत से नीचे रही और वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) तक तीन वर्षों के दौरान औसतन केवल 4.6 प्रतिशत रही। प्रतिकूल मौसम की दशाओं के कारण फसल के नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाओं के कारण कतिपय खाद्य पदार्थों की कीमतें बीच-बीच में प्रभावित हुई हैं।

सरकार आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, ताकि आम आदमी और निम्न आय वाले परिवारों के लिए उन्हें अधिक किफायती बनाया जा सके। इन उपायों में प्रमुख खाद्य पदार्थों से संबंधित बफर तैयार करना, इन वस्तुओं को समय-समय पर खुले बाजार में जारी करना, घरेलू खाद्य उपलब्धता बढ़ाने के लिए व्यापार नीतियों को अपनाना, स्टॉक सीमा निर्धारित करके और उसमें संशोधन करके जमाखोरी को रोकना, चावल, गेहूं का आटा, चना, मसूर दाल और मूंग दाल जैसी चुनिंदा खाद्य वस्तुओं को भारत ब्रांड के तहत नामित खुदरा दुकानों के माध्यम से रियायती कीमतों पर वितरित करना और घरेलू एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतों में समय-समय पर कमी करना शामिल है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख प्रस्तावों जिनमें दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन और राज्यों के साथ साझेदारी में 100 जिलों को शामिल करते हुए लागू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल है, से खाद्य पदार्थों में मूल्य दबाव कम होने की संभावना है।

(ख) सरकार ने मध्यम वर्ग की व्यय करने की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर के स्लैब और दरों में व्यापार स्तर पर बदलाव करने का भी प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आने और उनके हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के अन्य उपायों में बढ़ी हुई पेंशन योजनाएँ, किफायती आवास के लिए सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ और उद्यमियों हेतु वित्तीय सहायता शामिल हैं।

(ग) सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य समावेशी विकास है, जो गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने और कमजोर वर्गों के जीवन-यापन की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। नौकरी के अवसरों को बढ़ाने और आय सृजन करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, स्टैंडअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी विभिन्न रोजगार सृजन पहलों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, री-स्कील और अप-स्कील प्रशिक्षण हेतु कौशल भारत मिशन को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, सुदृढ़ पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक सुविधाओं में निरंतर सुधार, शहरी विकास, एमएसएमई का संवर्धन, कृषि और विनिर्माण जैसे को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे लोगों की रोजगार मिलेगा और उनकी क्रय शक्ति बढेगी।

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत व्यक्तिगत आयकर में प्रस्तावित महत्वपूर्ण सुधारों से कामकाजी और मध्यम वर्ग की आबादी की बचत और उपभोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा समय-समय पर कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में समुचित बदलाव किया गया है।

*****